1979-80 से अनौपचारिक शिक्षा का एक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, जिसमें 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारणों की वजह से औपचारिक स्कूलों में नहीं जा सकते, शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। यह कार्यक्रम इसके साथ-साथ औपचारिक स्कूलों से पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए भी है। इस कार्यक्रम को 704.00 करोड़ रुपए के परिव्यय से 8वीं योजना में जारी रखने के लिए संशोधित किया गया है। इस कार्यक्रम में शैक्षिक रूप से पिछड़े दस राज्यों और शहरी झुग्गी झोपड़ियों, पहाड़ी इलाकों, मरूस्थलीय क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के कामकाजी बच्चों की बहुलता वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार द्वारा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को स्वीकृत पद्धति से वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1992-93 के दौरान, भारत सरकार ने 13 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 2, 14,911 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए 45.17 करोड़ रुपए तथा 23000 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए 421 स्वैच्छिक एजेंसियों को 10.19 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता प्रदान की। चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम का बजट प्रावधान 108.67 करोड़ रुपए रखा गया है।

प्रौढ़ शिक्षा योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार

3381. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रौढ़ शिक्षा योजना में भ्रष्टाचार व्याप्त है जिसके परिणामस्वरूप प्रौढ़ शिक्षा योजना अपने उद्देश्य में पूरी तरह असफल रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा योजना के लक्ष्यों से संबंधित आंकड़ों की जांच और योजना के कार्य-निष्पादन की समीक्षा कराई है, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते। तथापि, प्रचलित आन्तरिक मूल्यांकन साक्षरता प्रारम्भ करने वालों पर आधारित होता है। इसमें ब्लाक/मंडल/तालुक/जिला स्तरों पर मास्टर प्रशिक्षकों एवं समन्वयकों के अपेक्षित केन्द्रों का नियमित, अनुवीक्षण तथा निरीक्षण किया जाना शामिल है।

इसके अलावा, सामाजिक विज्ञान प्रबंध संस्थानों विश्वविद्यालय विभाग आदि जैसे अभिकरणों द्वारा पूर्ण साक्षरता अभियान का बाह्य आंकलन/प्रभावी मूल्यांकन किया गया है। पूर्ण साक्षरता अभियानों का स्तर एवं प्रभावी मूल्यांकन करने के लिए अप्रैल, 1993 में या. अरूण घोष, भूतपूर्व सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में अलग से एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था। आशा है कि दल अपनी रिपोर्ट एक वर्ष के भीतर ही प्रस्तुत कर देगा।

राजकीय विद्यालय, पटेल नगर, नई दिल्ली के सेवा-निवृत्त दिवंगत शिक्षकों को देय भविष्य निधि/उपदान राशि का भुगतान किया जाना

3382. **श्री राम नरेश यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 4 सितम्बर, 1990 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 3119 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटेल नगर, नई दिल्ली स्थित राजकीय स्कूल के दिवंगत शिक्षकों की उपदान-राशि का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इन दिवंगत शिक्षकों के परिवारजनों या उनके दावेदारों को उक्त राशि का भुगतान कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां तो कब तक और भुगतान किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं?